E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2020; 2(1): 05-06
Received: 03-11-2019
Accepted: 07-12-2019

श्वेता सिंह
शोध छात्रा, आर्य कन्या डिग्री कालेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत।

Corresponding Author:
श्वेता सिंह
शोध छात्रा, आर्य कन्या डिग्री कालेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत।

भारत में नियोजित नगरीकरण की आवश्यकताः एक विमर्श

श्वेता सिंह

सारांश
''21वीं सदी में विकासशील देशों में शहरीकरण की क्रांति होने जा रही है। भारत इस क्रांति के अग्रिम पंक्ति में होगा। यह नगर में परिवारों और संस्थाओं के संकुलन के माध्यम से देश को अपनी समृद्धि दर के उन्नयन और गरीबी के निवारण का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। आगामी दशकों में नियोजित शहरीकरण भारत के विकास को एक विराट अवसर प्रदान करने जा रहा है।''

–प्रसन्ना के. मोहंती

मूल शब्दः नियोजित नगरीकरण, एक विमर्श, क्रांति, शहरीकरण

प्रस्तावना
नगरीय नियोजन जन समुदाय को विकास के केन्द्र में रखकर नगरीय शासन व्यवस्था के नए आयामों का विकास कर शहरी बुनियादी ढाँचे, सेवाओं और संसाधनों के उपयोग में सुधार से संबंधित है। सन् 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 31.04 प्रतिशत शहरों में निवास करता है जो 2030 तक 40 प्रतिशत एवं 2050 तक 50 प्रतिशत तक होने का अनुमान है। वर्तमान जनसंख्या से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के साथ ही नगरीय प्रशासन को भविष्य में होने वाली जनसंख्या वृद्धि को भी नियोजित करने के लिए तैयार होना होगा। बढ़ते शहरीकरण एवं जलवायु परिवर्तन से शहरों की संवेदनशीलता कई गुना बढ़ गई है। सतत विकास लक्ष्य–11 शहर और मानव बस्तियों को सुरक्षित, प्रतिरोधक और सतत बनाना एस.डी.जी. लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हमें नगरी नियोजन की ओर उन्मुख होना होगा। शहरों के उचित नियोजन व प्रबंधन से शहर प्रगति और समावेशी विकास का माध्यम बन सकते हैं।

महत्व एवं चुनौतियाः भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 31.08 प्रतिशत है जो कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर एवं ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि की तुलना में अत्यधिक है। 2030 तक देश की 40 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करेगी जिनका एकल घरेलू उत्पाद में योगदान में 75 प्रतिशत होगा। भारत के आर्थिक विकास में शहरी और नगरीय केन्द्रों का महत्व बढ़ रहा है। औद्योगिकरण और रोजगार के नए अवसरों ने नगरीकरण व शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति को बढ़ाया है जिससे शहरों में स्वच्छ पेयजल, आवास, चिकित्सा, परिवहन, महँगाई जैसी बढ़ती समस्याओं ने मानवीय गरिमा को भी हाशिएँ पर रख दिया है।
विडम्बना है कि एक तरफ लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और दूसरी ओर इस प्रकार के और शहरों को बेतहाशा विकसित किया जा रहा है। वर्तमान निवासियों से जुड़ी मूलभूत सेवाओं की कमी पर ध्यान देने के साथ ही हमें आयोजन को भविष्य में होने वाली जनसंख्या वृद्धि के अनुसार भी ढालने की जरूरत है। शहरों को इस स्तर तक सुविधाजनक बनाने की चुनौती है कि इसमें बढ़ती आबादी का रहना संभव हो सके।

नियोजित नगरीकरण की दिशा में प्रयासः आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाएं अस्तित्व में आई। परन्तु भारत में स्थानीय प्रशासन का अस्तित्व अपने परम्परागत स्वरूप में प्राचीन समय से विद्यमान रहा है। नगरीय शासन की प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में चण्डीगढ़, नोएडा आदि जैसे नियोजित शहरों का विकास, निवासियों के जीवन को सुविधाजनक बनाने की दिशा में अग्रसर है। स्मार्ट सिटी मिशन, जिसके अन्तर्गत 2020 तक 100 स्मार्ट शहर बनाने का लक्ष्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो प्रगति पर है।

जिसके अन्तर्गत जनसमुदाय को केन्द्र में रखकर शासन व्यवस्था के नये आयामों का विकास किया जा रहा है। 'डिजिटल टेक्नोलॉजी' का उपयोग कर शहरी बुनियादी ढाँचे, सेवाओं और संसाधनों के उपयोग में सुधार किया जा रहा है।

अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) आवास और शहरी मंत्रालय की प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य देश के 500 शहरों में बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना है जिससे सभी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, विशेष रूप से गरीबों और वंचित वर्ग के जीवन में दूरगामी परिवर्तन आए।

न्यूनतम सरकार अधिकलम प्रशासन का लक्ष्य रखते हुए सामान्य जन का जीवन आसान बनाने की दिशा में अनेक योजनाएं एवं प्रयास प्रगति पर है। नगरीय स्थानीय प्रशासन के साथ ही राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार को भी नगरीय नियोजक की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को और प्रभावी बनाने के लिए सक्रियता दिखानी होगी सहकारी संघवाद के साथ ही नगरीय स्थानीय प्रशासन की दिशा में सहकारी परिसंघवाद की ओर उन्मुख होना होगा।

नियोजित नगरीयकरण का प्रभावः शहर अपने लोगों के साथ विकसित होते हैं। वे आकांक्षाओं, सपनों और अवसरों से बने होते हैं। वे लाखों लोगों को वांछित जीवन शैली प्रदान करते हैं। अमृत व स्मार्ट सिटी जैसे कार्यक्रम शहरीय क्षेत्रों में जल और स्वच्छता पहुँच को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

संयुक्त राष्ट्र की 2018 की विश्व शहरीकरण संभावनाओं की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 2051 तक आधे से अधिक जनसंख्या शहरों में निवास करेगी। जनसंख्या के बढ़ते भार एवं संसाधनों की वर्तमान उपलब्धता के मध्य सामंजस्य नियोजित शहरों द्वारा बनाया जा सकता है। दीर्घकालिक तथा समृद्ध शहरों की योजना के लिए भारत के शहरों को तकनीकी रूप से उन्नत सामाजिक रूप से समावेशी और आर्थिक रूप से विविध होना होगा। नगरीय नियोजन की दिशा में चुनौतियाँ भी पर्याप्त है। नियोजन को प्रभावित करने वाले बुनियादी तत्व–कचरा, पानी, आवासक हरियाली, भूमि भाड़, आदि है। घनी आबादी और भौतिक सम्पत्तियों की वजह से जलवायु परिवर्तन, आपदाओं और संघर्षों के प्रति शहरों की संवेदनशीलता कई गुना बढ़ जाती है। शहरों का उचित नियोजन व प्रबंधन द्वारा ही शहर प्रगति और चिरस्थायी विकास का माध्यम बन सकते हैं।

निष्कर्ष

भारत ग्रामीण बहुलता से शहरीवत समाज में परिवर्तन के मध्य में है। बढ़ते शहरीकरण एवं जलवायु परिवर्तन से शहरों की संवेदनशीलता कई गुना बढ़ गई है। सतत विकास लक्ष्य–11 (शहर और मानव बस्तियों को सुरक्षित प्रतिरोधक और समावेशी बनाना) की प्राप्ति की दिशा में हमें नगरीय नियोजन की ओर उन्मुख होना होगा। पिछले कुछ वर्षों में, अधिकांश महानगर (चेन्नई, बंगेलूर, दिल्ली) आदि अपने संसाधनों की कगार पर पहुँच गये हैं एक शहर तभी विकसित हो सकता है जब उसके गाँव कायम रहें, इसलिए उप–शहरीय क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे में निवेश पर जोर दिया जाना चाहिए जिससे शहरों में होने वाली अनावश्यक भीड़ को घटाया जा सके। शहरी और ग्रामीण भारत को साथ–साथ विकसित करने के समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत में बढ़ते शहरीकरण को चुनौती के स्थान पर अवसर के रूप में लेना होगा। शहरों में उचित नियोजन एवं प्रबंधन से शहर प्रगति और समावेशी

संदर्भ

1. नंदा, डी (1998), भारत नगरीय प्रशासन, वाराणसी गंगा पब्लिशिंग हाउस।
2. प्रसाद, आर0 एन0 (2006), भारत में नगरीय स्थानीय स्वशासन, नई दिल्ली, मित्तल पब्लिकेशंस।
3. मोहंती, के0पी0 (2018), नगर एवं लोकनीति : भारत का शहरी एजेंडा, नई दिल्ली, SAGE पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
4. बसु, डी (2009) भारत का संविधान–एक परिचय, नई दिल्ली।
5. जनगणनाः 2011 (अंतिम आंकडे)
6. आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17
7. योजना दिसम्बर, 2019
8. अवस्थी, ए.सी., (1982) भारत में नगरीय प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।